

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2023—भाद्र 10, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. CT-8-0011-2023-Sec-1-पांच-(CT) (36).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्:—

- (i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तर्राज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे;
- (ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य से अधिक में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति नहीं करेंगे;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक की आवश्यकता होगी;
- (iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्यांक, अपने व्यवसाय के स्थान और राज्य, जिनमें ऐसी आपूर्ति करने का इच्छुक है, आम पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो आम पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अधीन होगा;
- (v) ऐसे व्यक्तियों को, खंड (iv) के अनुसार घोषित स्थायी खाता संख्यांक के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के लिए आम पोर्टल पर एक नामांकन संख्या प्रदान की गई है;
- (vi) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी;
- (vii) ऐसे व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो; और

- (viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चातवर्ती अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से विधिमान्य नहीं रह जाएगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. CT-8-0011-2023-Sec-1-पांच-(CT)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0011-2023-Sec-1-पांच-(CT) (36), दिनांक 1 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 1st September 2023

No. CT-8-0011-2023-Sec-1-V(CT)(36).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceeding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely:—

- (i) such persons shall not make any Inter-state supply of goods;
- (ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State;
- (iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
- (iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), address of their place of business and the State in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;
- (v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);
- (vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in a State;
- (vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and
- (viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.